उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी नहीं, आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष, वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 106 उद्यमों ने 4113 करोड़ रुपये का घाटा उठाया था। वर्ष 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 116 उपक्रमों द्वारा उठाया गया घाटा 5223 करोड़ रुपये था और वर्ष 1994-95 के दौरान 109 उद्यमों ने 4907 करोड़ रुपये का घाटा उठाया।

(घ) से (च) जी हां। वर्ष 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले 33 विनिर्माणकारी उद्यमों के अंतर्गत 51 उत्पादनकारी एककों ने वर्ष 1992-93 की तुलना में अपनी संस्थापित उत्पादन क्षमता के उपयोग में वृद्धि की थी। वर्ष 1994-95 के दौरान सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले 35 विनिर्माणकारी उद्यमों के अंतर्गत 60 उत्पादनकारी उद्यमों ने अपने संस्थापित उत्पादन क्षमता के उपयोग में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा वृद्धि की है। विगत तीन वर्षों अर्थात वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्षमता उपयोग का उद्यम-वार तुलनात्मक विवरण 19.7.1996 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1994-95 के खण्ड-1 के विवरण सं० 23 में दिया गया है।

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

729. **श्री रामजी लाल**: क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण नीति कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में राज्य-वार ऐसे कितने-कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है;

(ग) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में भी आरक्षण देने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में संविधान में कब तक संशोधन किया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) और (ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा और मेघालय को छोड़कर, सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण पूर्णतया राज्य का विषय है और चूंकि आरक्षण को प्रत्येक राज्य द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है इसलिए केन्द्र सरकार के पास प्रत्येक श्रेणियों में उन व्यक्तियों की संख्या का रिकार्ड नहीं है जिन्हें राज्य-वार लाभान्वित किया है।

(ग) और(घ) यह मामला विचाराधीन है।

Excess Sugar Production

730. DR. D. VENKATESHWAR RAO:. Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether there has been excess production of sugar during current calendar year and Government have been urged to give clearance for export of additional sugar;

(b) if so, whether Government have given the directive;

(c) the extent to which additional sugar will be exported;

(d) whether Indian sugar mills will begreatly relieved if exports are allowed;

(e) whether Government's decision to delay in fixing the levy price of sugar has affected sugar industry; and

(f) by when a final decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Until the close of the sugar season 1995-96 it is not possible to say how much sugar will be exported.

(d) Yes, Sir.

(e) No, Sir. The ex-factory price of levy sugar is applicable retrospectively from the beginning of the sugar season.

(f) The ex-factory prices for 1995-96 season have already been notified on 14.5.1996.